विश्व पंचायत की जबरदस्त नाकामी

मौसम के बदलते मिजाज के यक्ष प्रश्न पर पूरब-पश्चिम फिर आमने-सामने

जलवायु

प्रभात कुमार रॉय

मौसम के बदलते खतरनाक मिजाज़ की गहन गंभीर चिंता के साथ डेनमार्क के एक शहर कोपनहेगन में दुनिया भर के 198 मुल्कों की एक पंचायत अनेक दिनों तक जुटी रही। यह विश्व पंचायत केवल 'कोपनहेगन एकार्ड' के तहत एक प्रस्ताव पारित कर पाई। जिसकी 'इंटरनेशनल कानून' के अंतर्गत कदाचित किसी देश पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अमेरिका की अगुवाई में भारत, ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर एक दस्तावेज तशकील किया, जिसे विकासशील मुल्कों की हिमायत हासिल नहीं हो पाई। इस दस्तावेज में अहद किया गया कि तकरीबन 30 बिलियन डालर की इमदाद फौरी तौर पर विकासशील मुल्कों को कार्बन उत्सर्जन कम करने के काम में प्रदान करेंगे। कोपनहेगन पंचायत को एक दिन के लिए आगे भी बढ़ाया गया। अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा ने अपना पूरा जोर लगाया। भारत का प्रतिनिधिमंडल तो एयरपोर्ट से वापस बुलाया गया। किंतु इस सारी कवायद के बावजूद कोपनहेगन पंचायत कतई कुछ भी ठोस नहीं निकाल पाई।

अमेरिका यूरोप, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका प्रायः सभी देशों के नुमाइंदों ने जोरदार बहस अंजाम दी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान निरंतर गति से बढ़ रहा है। वजह तो सभी जानते हैं कि विषाक्त ग्रीन हाउस गैसें अर्थात कार्बनडाइआक्साइड नाइट्रस आक्साइड, मीथेन, सल्फरडाइआक्साइड कार्बनमोनोआक्साइड, ब्लैककार्बन जैसी गैसों के वाल्यूम में धरती के पर्यावरण में खतरनाक स्तर तक बढ़ोत्तरी हो चुकी है। पृथ्वी के वातावरण में तापमान में वृद्धि का सीधा नतीजा सामने आ रहा है कि ऊंचे-ऊंचे पर्वत शिखरों के बर्फानी ग्लेशियर तेजी के साथ पिघल रहे हैं और दुनिया भयावह संकट के कगार तक पंहुच गई है। यही हाल जारी रहा तो आगामी 30 वर्षों में दुनिया को सरसब्ज़ करने वाली तकरीबन सभी नदियां दम तोड़ देंगी। जिनमें हमारी पतित पावनी गंगा मां भी शामिल है। समुद्र का जलस्तर कई मीटर तक बढ़ जाएगा और सागर किनारे बसे अनेक शहर और मुल्क तो जल समाधि ले लेंगे। दुनिया भर में अनुमानतः 20 करोड़ इंसानों को अपनी रिहाइशी धरा से विस्थापित होना होगा। ग्लोबल वार्मिंग के कहर से दुनिया को बचाने की मुहिम के तहत ही जापान के एक शहर क्योटो में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके नतीजे के तौर पर 'क्योटो प्रोटोकोल' वजूद में आया था। हालांकि इस इंटरनेशनल समझौते को अमेरिका और आस्ट्रेलिया के दस्तखत हासिल नहीं हो पाए। इसीलिए क्योटो प्रोटोकोल' को 20 वीं सदी की एक भव्य कूटनीतिक विफलता करार दिया गया। केवल विकासशील जी 77 देशों ने इस पर अपनी शासकीय मोहर लगाई थी। 'क्योटो प्रोटोकोल' की मियाद सन् 2012 में खत्म हो रही है। इसी कारण से क्लाइमेट चेंज के सवाल पर एक नए अधिक व्यापक इंटरनेशनल समझौता तशकील करने की जद्दोजहद जारी है। 'कोपेनहेगन सम्मेलन' भी दरअसल इसी मकसद को हासिल करने का महज एक मकाम रहा। अफसोस कि अमेरिका और यूरोप के अमीर मुल्कों के अहंकार और हठधर्मिता के जारी रहते यह मकसद हासिल न हो सका। वस्तुतः इस सम्मेलन के प्रमुख बिंदु रहे, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाने के ठोस लक्ष्य निर्धारित करना। कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था करना। ऊर्जा उत्पादन की कम कार्बन आधारित तकनीक मुहैया कराना। क्लाइमेट चेंज के अनिवार्य परिणामों से निपटने की योजनाएं बनाना। क्लाइमेट वैज्ञानिकों के अनुसार सन् 2050 तक कार्बन डाइआक्साइड की प्रति व्यक्ति मात्रा को दो टन तक सीमित किया जा सके तो क्लाइमेट चेंज के कहर से काफी कुछ बचा जा सकता है। इसका समुचित अर्थ है कि सन् 2000 में विकसित देशों का जो कार्बन उत्सर्जन स्तर था, उसे उन्हें सौ फीसदी तक घटाना होगा। साथ ही विकासशील देशों को भी कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी करनी होगी। अमेरिका में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की मात्रा तकरीबन बीस टन रही है। अमेरिका की तुलना में भारत में प्रति व्यक्ति मात्रा डेढ़ टन कार्बन उत्सर्जन ही हो रहा है। भारत और चीन जैसे विकासशील देशों का तर्क रहा है कि बिगड़ते हुए मौसम का मसला दरअसल अमेरिका, यूरोप और अन्य विकसित देशों की देन है और इसके समुचित समाधन की अधिक जिम्मेदारी भी इन्हीं मुल्कों की अधिक है। बहुत कम प्रदूषण वाली ऊर्जा के निर्माण की तकनीक तो बहुत अधिक महंगी है। अतः अमेरिका जैसे अमीर देशों को प्रौद्योगिक और माली सहायता के लिए आगे आना चाहिए। तभी भारत जैसे विकासमान देश अपनी गतिशील विकास दर का तालमेल कम कार्बन उत्सर्जन के साथ बिठा सकते हैं। भारत जैसे गरीब मुल्कों को तरक्की करने के लिए बिजली की बहुत अधिक आवश्यकता है। हम अधिकतर बिजली बनाते हैं कोयले, जीवाश्म ईंधन से बस यही वजह हमारे देश द्वारा अधिक कार्बन उत्सर्जन करने की रही है। मौसम के मिजाज में खतरनाक बदलाव के लिए भारत और चीन जैसे विकासशील देश अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों को पूर्णतः जिम्मेदार मानते आए हैं और अमेरिका की कयादत में ताकतवर अमीर मुल्क भारत और चीन जैसे विशाल आबादी वाले देशों पर इस विनाशकारी कहर की जिम्मेदारी आयद करने में जुटे रहे हैं। मौसम के बदलते मिजाज़ के यक्षप्रश्न पर पूरब और पश्चिम फिर से आमने सामने तनकर खड़े हुए हैं।

भारत के बारे में एक चीनी राजदूत ने कहा था कि युगों-युगों पूर्व एक भी सैनिक को भेजे बिना भारत तो चीन और जापान सहित पूरे दक्षिण एशिया पर अपनी सांस्कृतिक विजय पताका फहरा चुका है। आज पुनः भारत को अपनी संस्कृति के विस्मृत मंत्रों को साकार रूप प्रदान करके दुनिया भर के लिए प्रकृति को उसकी पुरानी लुप्तप्रायः चितवन लौटाने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। प्रकृति के साथ अद्भुत सामंजस्य बिठाने और उसके साथ एकाकार हो जाने का गुरुमंत्र सदियों पूर्व हमारे योगियों-मुनियों ने विश्व को प्रदान किया था। आज उसी प्राचीन मंत्र को पुनः जीवन में उतारना ही होगा। क्या हम भारतवासी अपनी पावन धरा पर उजड़ते जंगलों को फिर से हरा-भरा कर पाएंगे? क्या हम नई कारों के माडलों के लिए अपने आत्मघाती क्रेज परित्याग कर पाएंगे? यदि नहीं तो फिर अपनी मां गंगा को और पर्वतराज हिमालय के अविरल बर्फानी ग्लेशियरों को कैसे बचा लेंगे? क्या हम विश्व गुरू होने का मकाम पुनः पा सकेंगे? अन्यथा ग्लोबल मार्केट के भयावह दौर में अपना सब कुछ कहीं गंवा तो नहीं देंगे?

Reproduced by www.hobbyshobby.com with author permission